ओलम्पिक की तैयारी के लिए राजस्थान टॉप्स योजना लागू- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सब जूनियर व जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैम्पियनशिप के समापन समारोह में भाग लिया

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 17 नये ''खेलो इंडिया'' केन्द्र शुरु किये जा रहे हैं तथा 1786 खिलाड़ियों को 40.12 करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने योगासन चैम्पियनशिप विजेता पश्चिम बंगाल, द्वितीय स्थान पर रहे हरियाणा, तीसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अलंकार पीजी कॉलेज में 51वीं सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के समापन समारोह में भाग लिया।

जयपुर, 6 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और ऋषियों की अनमोल धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ, संयमित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने आमजन से आ ान किया कि वे नशे की लत को छोड़ें और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हुए विकसित भारत-विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री मंगलवार को अलंकार पीजी कॉलेज में 51वीं सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि एकाग्रता को बढ़ाने, निर्णय क्षमता को मजबूत करने और जीवन में सकारात्मकता लाने में योग की अहम भूमिका है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए राजस्थान युवा नीति-2025 जारी की है। प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलम्पिक खेलों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान टॉप्स योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 नए ''खेलो इंडिया केन्द्र'' शुरू किए जा रहे हैं। वहीं, 1 हजार 786 खिलाड़ियों को 40 करोड़ 12 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योगासन चैम्पियनशिप के विजेता पश्चिम बंगाल, द्वितीय स्थान पर रहे हरियाणा और तृतीय स्थान पर रहे महाराष्ट्र को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान राजस्थान की टीम ने संगीतमय योगासन की प्रस्तुति दी।

हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

जयपुर, 6 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के पांच साल पुराने दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को बिना किसी छूट के 75 साल की उम्र होने तक जेल में रखा जाए। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस को खारिज करते हुए, अभियुक्त पिंटू डागर

- अदालत ने कहा, पत्नी और बच्चे की हत्या सोची समझी साजिश नहीं थी तथा पाँच साल जेल में अभियुक्त का व्यवहार शांत रहा है।

की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि घटना पहले से सोची-समझी साजिश नहीं है। अभियुक्त पन्द्रह साल से विवाहित था और उसके दो बेटे थे। घटना घर के भीतर अचानक हुई कहासुनी का नतीजा थी और इस दौरान उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। घटना के समय छह माह का बच्चा गोद में था और उसे भी जानलेवा चोट लग गई। बीते पांच साल से जेल में उसका व्यवहार शांत रहा है और उसमें सुधार की गुंजाइश मौजूद है।

राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि नियमानुसार, अभियुक्त की फांसी की सजा को कंफर्म किया जाए। वहीं, अभियुक्त की ओर से एडीजे कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। दोनों मामलों की संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।

पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने वीआईएफ निदेशक का पद संभाला

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से पहले 2014 में डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउण्डेशन (वी आई एफ) के प्रमुख थे

- अजीत डोभाल ने 2009 में इस फाउण्डेशन की स्थापना की थी। यह डिप्लोमैटिक कम्यूनिटी समुदाय के साथ काम करता है तथा राजनीतिक मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा, ज़ियोपॉलिटिक्स और सभ्यता से जुड़े मुद्दों पर पॉलिसी ब्रीफ व रिसर्च तैयार करता है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) जनरल अनिल चौहान ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) के निदेशक का पद संभाल लिया है। भारत के शीर्ष सैन्य पद से सेवानिवृत्त होने के कुछ ही महीनों बाद, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति के क्षेत्र में वापसी हुई है।

चौहान ने 5 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित ''पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक'' की जिम्मेदारी संभाली। वीआईएफ ने पूर्व सीडीएस का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति संगठन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। फाउंडेशन ने पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. अरविंद गुप्ता के कार्यकाल को भी याद किया, जिन्होंने इससे पहले फाउंडेशन का नेतृत्व किया था।

भारत के दूसरे सीडीएस चौहान 30 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने तीन साल से अधिक समय तक सीडीएस, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया।

उन्हें 30 सितंबर 2022 को सीडीएस नियुक्त किया गया था। इससे पहले, वे पूर्वी सेना के कमांडर और सैन्य संचालन के महानिदेशक के पद पर रह चुके थे। उनके कार्यकाल में सैन्य सुधारों, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और प्रस्तावित थिएटर कमांड स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

2009 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा स्थापित वीआईएफ, डिप्लोमैटिक कम्युनिटी के साथ काम करता है और रणनीतिक मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिओपॉलिटिक्स और सभ्यता से जुड़े मुद्दों पर पॉलिसी ब्रीफ व रिसर्च तैयार करता है। इसकी कार्यकारी समिति की अध्यक्षता एस. गुरुमूर्ति करते हैं।

वीआईएफ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति, जिओपॉलिटिक्स और सैन्य बदलाव के क्षेत्र में चौहान का अनुभव फाउन्डेशन की रिसर्च और रणनीतिक बातचीत को और मजबूत करेगा।

इस नियुक्ति ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि डोभाल खुद 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से पहले वीआईएफ का नेतृत्व कर चुके थे। इससे भारत की रणनीतिक नीति व्यवस्था में चौहान की अगली भूमिका को लेकर दिलचस्पी और बढ़ गई है।

300 विपक्ष के सांसदों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी-शाह सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप है।

कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार और भाजपा सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की अगुवाई की है।

राहुल गांधी ने ''वोट चोरी'' को देशद्रोह बताते हुए वादा किया है कि सही समय आने पर पूरे घटनाक्रम में शामिल मुख्य लोगों, जिनमें, मोदी, शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भागवत और अन्य लोग शामिल हैं, को बख्शा नहीं जाएगा।

उनका कहना है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने और लोगों के वोट तथा सरकार चुराने के लिए इन सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

सीबीआई ने पंजाब सीएमओ के कैंप ऑफिस पर सर्च शुरु की

मुख्यमंत्री भगवंत मान खुलकर विरोध में उतरे, ईडी ने मुख्यमंत्री के साढू को जांच के लिये तलब किया

- पंजाब -हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपी थी। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देकर तत्काल सुनवाई की याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में उसे खारिज कर दिया।

चंडीगढ़ , 06 अक्टूबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मंगलवार शाम सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित सीएम कैंप ऑफिस समेत कई जगह सर्च की। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं, वहीं भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साढ़ू को भी तलब कर लिया है।

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में फैले कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपी थी। उच्च न्यायालय के आदेश मिलने के बाद मंगलवार को सीबीआई और ईडी सक्रिय हो गई। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में इन दिनों ईमानदार मुख्यमंत्री के नाम से बोर्ड एवं होर्डिंग लगाकर प्रचार किया जा रहा है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस में मंगलवार शाम छापा मारा। सीबीआई की टीमें मोहाली और संगरूर भी पहुंचीं। संगरूर में सीएम के साढ़ू राजबीर सिंह घुम्मन के घर और मोहाली में उनके भाई के घर पर जांच की। देर रात तक सीबीआई की कई स्थानों पर सर्च जारी रही। इस बीच उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब सरकार ने उच्चतम न्यायालय में तत्काल सुनवाई की याचिका दायर की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने दोपहर बाद खारिज कर दिया।

आतंकी अफ़ज़ल गुरु के घर के पास अवैध शैड ध्वस्त

श्रीनगर, 06 अक्टूबर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जिला प्रशासन ने मंगलवार को गुलनार पार्क के पास स्थित आतंकी अफजल गुरू से संबधित मकान के आस पास बने शेड और अन्य ढ ांचों को नष्ट कर दिया।

संसद हमले में लिप्त अफजल गुरू को नौ फरवरी 2013 में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।

बताया जा रहा है, जिस मकान से संबधित शेड व अन्य ढ ांचों को गिराया गया है,उक्त मकान में अफजल गुरू की पत्नी और उसका बेटा रहते हैं।

इन ढांचों को गिराए जाने की कार्रवाई के समय मजिस्ट्रेट के अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

जानकारी के लिए बता दें कि यह डेयरी फार्म है, जो आतंकी अफजल गुरु के परिवार से संबंधित था। जहां ये डेयरी फार्म बना था वो सरकारी जमीन थी।

अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्ज़ैन को फिज़िक्स में नोबेल पुरस्कार मिला

यह पुरस्कार अंतरिक्ष से धरती तक पहुंचने वाले बेहद ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कण की खोज के लिये दिया गया

- वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्ज़ैन का मानना है कि साउथ पोल की बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो कहे जाने वाले कणों को ट्रैक करने के लिये किया जा सकता है।

वाशिंगटन, 06 अक्टूबर। बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को साल 2026 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आइसक्यूबन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में अहम योगदान और अंतरिक्ष से धरती तक पहुंचने वाले बेहद ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कण की खोज के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें यह सम्मान दिया है। हाल्जेन ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा अमेरिका में बिताया।

दिसंबर 2026 में स्वीडन के स्टॉकहॉम में फ्रांसिस हाल्जेन को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल, डिप्लोमा और 11.5 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि भी मिलेगी।

आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसका विचार इस साल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले फ्रांसिस हैल्जेन ने दिया है, दूर अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो को ट्रैक करती है।

आइसक्यूब द्वारा लगातार इकट्ठा की जाने वाली न्यूट्रिनो इंटरैक्शन से शोधकर्ताओं को उन हिंसक स्थितियों के बारे में नई जानकारी मिलेगी, जिनमें हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो बन सकते हैं, और इससे पहले से अज्ञात ब्रह्मांडीय घटनाओं का भी पता चल सकता है।

2026 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले फ्रांसिस हैल्जेन ने महसूस किया कि साउथ पोल की बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो कहे जाने वाले कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। उनकी सोच और वैज्ञानिक नेतृत्व आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के लिए बहुत अहम रहे हैं।

कांग्रेस काफी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित, कई नेता ऑल इंडिया रेडियो के परिसर में धरने पर बैठे हैं, जो चुनाव आयोग कार्यालय के बगल में स्थित है।'' एक कांग्रेस नेता ने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम पर तंज कसते हुए, इस धरने को 'आकाशवाणी से जन की बात' कहा।

विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सत्ताधारी भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया है। इससे पहले, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और डैरेक ओ'ब्रायन समेत, विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जा रहे मार्च को रोक दिया था। विरोध कर रहे सांसदों को बसों में ले जाया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष मतदान के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। उन्होंने कहा, ''यह विरोध जारी रहेगा। हम आपके वोट और आपकी आजादी की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। देश के लोग कह रहे हैं कि उनके बहुत से वोट हटा दिए गए हैं और वोटों की चोरी हो रही है। हम उनके वोटों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।''

पीटीआई भर्ती-2022 की धांधली पर राज्य सरकार 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जवाब पेश करेगी

मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई इस प्रकरण की सुनवाई में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा

-यादवेन्द्र शर्मा-

- याचिकाकर्ता का कहना है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने 3 मार्च 2025 को आदेश में कहा था कि इस भर्ती धांधली में दर्ज 39 एफआईआर की जांच व एसओजी के निष्कर्षों की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए।
- याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जोधपुर हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए थे कि जिन 243 अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर दस्तावेज सत्यापन हुआ था, और जिन्हें मैरिट सूची में शामिल किया गया था, उनका रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया जाए। जिन लोगों को नियुक्तियां दी जाएं, उनकी सूची कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

जयपुर, 6 अक्टूबर। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में शारीरिक शिक्षक (पी.टी.आई.) भर्ती-2022 में धांधली और फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ दायर 39 एफ.आई.आर. पर राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ के समक्ष सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि हम इस मामले में जवाब पेश करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने इस मामले को 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के लिये सूचीबद्ध किया है।

अदालत में याचिकाकर्ता प्रेमाराम गोलिया व अन्य की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी.सिंह व सहायक अधिवक्ता आशीष पूनियां ने कहा कि 3 मार्च 2025 को जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि इस मामले की जांच के बाद एक कमेटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति अथवा उन्हें हटाने के संबंध में निर्णय ले तथा जिन लोगों को नियुक्तियां दी जाएं, उनकी सूची कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि 39 एफआईआर में हुई जांच व एसओजी के निष्कर्षों की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा जिन 243 अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर दस्तावेज सत्यापन हुआ था, और जिन्हें मैरिट सूची में शामिल किया गया था, उनका रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अदालत ने सभी 259 अभ्यर्थी का लंबित ''स्टेटस'' बताने के लिए भी कहा था कि इनका दस्तावेज सत्यापन हुआ है अथवा नहीं, अगर कागजात आए हैं तो क्या-क्या आए हैं।

जैसा कि विदित है कि एस.ओ.जी. ने 10 जून 2024 को इस मामले की जांच करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें साफ लिखा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से फर्जी डिग्रियां लेकर नौकरी हासिल की गई है। इनमें से 145 अयोग्य अभ्यर्थियों के पास ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, जबकि अंतिम सूची में मात्र 6 ऐसे योग्य अभ्यर्थी थे, जिनके पास इस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। करीब 173 ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी थे, जिन्होंने परीक्षा के बाद डिग्रियां ली थीं। कुछ लोग ऐसे थे, जिनके पास ऐसी यूनवर्सिटी की डिग्रियां थीं, जो एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थीं। इसी प्रकार 183 अयोग्य अभ्यर्थी ऐसे थे, जिनके बी.पी.एड. डिग्री में 45 प्रतिशत से भी कम अंक आए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि 1259 अयोग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति दी गई है, इनमें से 1230 लोग ऐसे हैं, जिनके आवेदन और डिग्रियां में अंक प्रतिशत व रोल नंबर की गड़बड़ियां हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी खुद माना है कि करीब 1502 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनके दस्तावेज सत्यापन में धांधली पाई गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2024 में हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मैरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 39741 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परंतु पी.टी.आई. भर्ती में 2000 लोगों को बिना मैरिट लिस्ट जारी किए ही सीधे चयनित मान लिया गया।

इस मामले में कई तकनीकी कारणों और जजों का रोस्टर बदलने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। मंगलवार को इस मामले को न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ के समक्ष उल्लेखित (मेंशन) किया गया, ताकि मामले की तुरंत सुनवाई हो सके। इस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत ने सरकार को 1 सप्ताह का समय देते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दी।

नंदीग्राम में 79.39 प्रतिशत मतदान

कोलकाता, 06 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल के दो बेहद चर्चित और संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद के रेजीनगर, में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपचुनाव संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान प्रतिशत काफी ऊंचा रहा। नंदीग्राम में 79.39 प्रतिशत और रेजीनगर में

- तीखी बहस के बाद पुलिस ने विधायक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया।

78.42 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

रेजीनगर में मतदान के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब विधायक हुमायूं कबीर की अपनी पार्टी के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई। कबीर ने पुलिस पर मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के इशारे पर काम करने और मतदाताओं को डराने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कथित तौर पर लोगों से पुलिस की ज्यादतियों का डंडों से विरोध करने का भी आ ान किया था।

वायरल हुए घटना के दृश्यों में पुलिसकर्मियों को कबीर को शर्ट से पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए देखा गया। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सचिन मक्कड़ ने स्पष्ट किया कि कबीर न तो उम्मीदवार थे और न ही अधिकृत चुनाव एजेंट, इसलिए उनका मतदान केन्द्रों के आसपास घूमना नियमों का उल्लंघन था। कबीर पर मतदाताओं को प्रभावित करने और भड़काने का आरोप है।

नवीन पटनायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का संकेत नहीं है। देव ने कहा, ''हमारे नेता नवीन पटनायक का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि हम न तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और न ही एनडीए के साथ।''

लेकिन भाजपा इससे चिंतित नजर आ रही है। भगवा पार्टी ने आज आरोप लगाया कि कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी बीजेडी अब गठबंधन के लिए सहयोगी तलाश रही है। भाजपा ने इसके पीछे आंतरिक दबाव और कुछ नेताओं द्वारा दूसरे विकल्प तलाशने की बात कही।

केन्द्र में किसी समय अनौपचारिक समर्थन पर आधारित रहे भाजपा और बीजेडी के संबंध पिछले विधानसभा चुनावों के बाद काफी खराब हो गए हैं। बीजेडी अब भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और ओडिशा में मतदाता सूचियों को लेकर चुनाव आयोग के कामकाज की लगातार आलोचना कर रही है। बीजेडी का दावा है कि राज्य में 20 से 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

ओडिशा के बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में, जहां 24 साल के बीजेडी के शासन के बाद, अब भाजपा सत्ता में है, बीजेडी द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति को पूरी तरह छोड़ने की संभावना कम है, लेकिन यह संभावना लगातार बढ़ रही है।

मुद्दों के आधार पर दोनों दलों के बीच सहयोग बढ़ा है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेडी ने संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। इसके अलावा, बीजेडी परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर विपक्ष के व्यापक मंचों में भी शामिल हुई है।

अगर भाजपा का दबदबा लगातार बना रहता है और शासन तथा चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता की चिंताएं बढ़ती हैं, तो पटनायक भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने के लिए रणनीतिक गठबंधन की ओर बढ़ सकते हैं।

हालांकि, निकट भविष्य में बीजेडी के औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि पार्टी क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जोर देती रही है और राष्ट्रीय दलों को लेकर उसका रवैया हमेशा सावधानी वाला रहा है।

कांग्रेस के लिए गठबंधन के कई फायदे होंगे। इनमें ओडिशा में भाजपा को अधिक प्रभावी तरीके से चुनौती देने के लिए वोटों का एक-दूसरे को हस्तांतरण, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की मजबूत छवि और ऐसे राज्य में फिर से राजनीतिक महत्व हासिल करने का मौका शामिल है, जहां कांग्रेस लंबे समय से कमजोर रही है।

लेकिन इसके नुकसान भी होंगे। कांग्रेस को बीजेडी को प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में अधिक महत्व देना पड़ सकता है। इससे पुराने राजनीतिक संघर्षों को याद रखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो सकती है और पार्टी पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लग सकता है।

जहाँ तक बीजेडी को होने वाले फायदों का प्रश्न है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक मंच, भाजपा के खिलाफ साझा संसाधनों का इस्तेमाल और ओडिशा से जुड़े मुद्दों पर अधिक राजनीतिक दबाव बनाने की क्षमता हासिल हो सकेगी।

लेकिन उसे नुकसान ज्यादा बड़े हो सकते हैं। उसकी स्वतंत्र क्षेत्रीय पहचान कमजोर हो सकती है, समान दूरी की नीति पसंद करने वाले मतदाता नाराज हो सकते हैं और भविष्य में सत्ता में साझेदारी की स्थिति में कांग्रेस के जूनियर पार्टनर बनने का खतरा हो सकता है।

शिक्षा विभाग को महिला प्रबोधक के नाम से ''देवी'' हटाना भारी पड़ा

जयपुर, 6 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला प्रबोधक के सर्विस रिकॉर्ड में लंबे समय तक नाम सही नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही, अदालत ने शिक्षा विभाग पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश शकुंतला देवी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि छोटी सी लिपिकीय गलती को

- हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई व दस हजार रूपए का हर्जाना लगाया।

सुधारने के लिए याचिकाकर्ता को सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। यह विभाग की उदासीनता का ज्वलंत उदाहरण है।

याचिका में अधिवक्ता ताराचंद शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का प्रबोधक पद पर चयन हुआ था। उसका शैक्षिणक प्रमाण पत्र, आधार और अन्य दस्तावेजों में भी शकुंतला देवी शर्मा ही नाम है, लेकिन नियुक्ति आदेश और सेवा पुस्तिका में देवी शब्द हटाकर केवल शकुन्तला शर्मा लिख दिया गया। जुलाई 2023 में याचिकाकर्ता ने नाम सुधारने का अभ्यावेदन दिया और कई रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन विभाग ने न तो सुधार किया और न ही कोई जवाब दिया। मजबूर होकर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो विभाग अचानक सक्रिय हो गया और अप्रैल 2025 में नाम सुधार का आदेश जारी कर दिया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908